नगर निगम के लिये शर्मनाक : जलभराव से 'निपटने' का बीड़ा उठाया उपायुक्त ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) यहां तैनाती के अपने छोटे से कार्यकाल में उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने भली-भांति समझ लिया है कि शहर में जल भराव को रोक पाना नगर निगम के वश की बात नहीं है। इनसे पहले यहां तैनात रही मंडलआयुक्त जी अनुपमा ने भी इस सच्चाई को पहचानते हुए तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन निगम अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें उनसे पूछा गया था कि जलभराव से निपटने के लिये क्या उपाय किये गये हैं? उस बैठक में निगमायुक्त अनिता यादव ने खुद न आकर अपने नुमाइंदे को भेजा था। मंडलायुक्त के सवाल का जवाब देते हुए एक्सईएन धर्म सिंह ने बताया था कि शीघ्र ही नालों की सफ़ाई के लिये टेंडर जारी करने वाले हैं।

मंडलायुक्त ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि बरसात का मौसम सिर पर आ चुका है और तुम लोग अभी टेंडर ही जारी करने जा रहे हो। जवाब में धर्म सिंह ने कहा था कि बस, एक दो दिन में टेंडर जारी हो जायेगा और उसके बाद तुरन्त काम हो जायेगा। वाकई 'काम' हो गया। क्या काम हो गया? टेंडर पास हो गये, बिल भी बन कर पास हो गये, रुपयों की बंदरबांट हो गई जबकि शहरवासी जलभराव से जूझते रहे। निगम अधिकारी केवल इतना ही काम जानते हैं जो वे हर साल करके दिखाते आ रहे हैं।

अब देखना है कि उपायुक्त महोदय जलभराव को बाढ़ का नाम देकर किस प्रकार इस मुसीबत से शहरवासियों को राहत दिला पायेंगे? इसे लेकर हाल ही में उपायुक्त ने ज़िले भर के अफ़सरों की बैठक बुलाई थी। इसमें जलभराव के 25 स्थान चिन्हित करके उन पर 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिये हैं। उनकी सहायता के लिये पूरा पुलिस विभाग, थानों के एसएचओ तथा तहसील के तमाम कर्मचारी तैनात होंगे। सिविल डिफेंस के 100 वालेंटियर भी तैनात किये हैं।

कहने को नगर निगम का तमाम स्टाफ़ भी इस काम में जुटेगा, लेकिन उनकी क्षमता तो केवल टेंडर पास करके कमीशन खाने तक ही सीमित रहती है। अजरोंदा चौक पर जब दो-दो फ़ुट पानी भर जाता है तो निगम की ओर से सकर मशीनें यानी ऐसे ट्रैक्टर टैंकर जो पानी सक करके ले जाते हैं, को लगा दिया जाता है। इसके लिये मोटे-मोटे बिल बनते हैं और अच्छा-खासा कमीशन अफ़सरों की जेबों में आ जाता है।

इसलिये जलभराव का होना उनके लिये मुनाफ़े का धंधा है। बिजली विभाग वालों को भी आपूर्ति जारी रखने की हिदायत दी गई है ताकि डिस्पोजल की मोटरें चलती रह सकें। यहां समझने वाली बात यह है कि आंधी, तूफान, बारिश में बिजली की सप्लाई बनाये रखना इस विभाग के वश में नहीं है। इसी के मद्दे नज़र डिस्पोजलों पर जनरेटरों की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त को चाहिये कि इन जनरेटरों को सुचारु रखने को सुनिश्चित करें जो आम तौर पर संकट काल में चल नहीं पाते।

सारी बैठक में एक ही अक्ल की बात सामने आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एस्कॉर्ट फैक्ट्री के सामने रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है। वास्तव में यही व्यवस्था सर्वोत्तम भी है। लेकिन यह तभी सर्वोत्तम हो सकता है जब इसके निर्माणकर्ता भ्रष्ट एवं निकम्मे न हों। कहने की जरूरत नहीं कि पानी स्वत: ढलान की ओर बढता है। मूर्ख वास्तुकारों द्वारा बनाये गये नक्शों एवं अवैध निर्माणों ने पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया। इसके चलते अमृत समान बरसाती पानी जनता के लिये मुसीबत बन गया।

बरसात से पहले उफनते सीवरों को तो सम्भाल लीजिये!

बरसात का पानी तो सड़कों पर भरेगा सो भरेगा उसमें जो सीवर का गंध घुलेगा वह मुसीबत को और भी बढ़ा देगा। सीवर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये बरसात के आने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसे तो हर समय ही व्यवस्थित रहना चाहिये। उसके अलावा बिना बरसात के भी जहां-जहां पानी खड़ा है उसे आज भी सम्भाला जा सकता है। बाटा मोड़ से दिल्ली की ओर चलें तो सड़क किनारे सदा ही पानी खड़ा रहता है। इसी तरह बल्लबगढ़ से पलवल की ओर चलें तो जेसीबी प्लांट के सामने आज भी दो-दो फ़ीट पानी खड़ा है। इसके अलावा और भी ऐसे अनेकों प्वाइंट हैं जिन्हें बरसात से पहले सम्भाल लेना चाहिये।

25 मैजिस्ट्रेट व पुलिस कैसे जलभराव रोकेंगे? सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस वाले खड़े पानी को कैसे खदेड़ेंगे? अब तक तो प्रदर्शनकारी भीड़ को तो इनके द्वारा खदेड़े जाते देखा गया है परन्तु पानी को ये बेचारे कैसे खदेड़ पायेंगे? हां, अब तक तो पुलिस वालों को, जाम में फंसे वाहनों को किसी तरह निकालने में मदद करते तो देखा गया है। बरसते पानी की परवाह न करते हुए घुटने-घुटने तक पानी में वाहनों को धक्का लगाते हुए भी पुलिस वालों को देखा गया है।

परन्तु मैजिस्ट्रेट साहब यहां क्या कर पायेंगे समझ से परे है। हां, यदि पर्याप्त समय रहते जलभराव से निपटने के उपाय एवं सुझाव उनसे पूछे जाते तो वे जरूर कुछ काम की बात बता सकते थे। वैसे जहां तक काम की बात का सवाल है नगर निगम वालों को वह कभी समझ आ ही नहीं सकती। जल भराव से निपटने के अनेकों उपाय 'मज़दूर मोर्चा' अनेकों बार प्रकाशित कर चुका है जिन पर कोई विशेष खर्चा भी नहीं। परन्तु बिना खर्चे वाले काम से निगमकर्मियों की जेब में क्या आयेगा? इसलिये उनके लिये तो हर वर्ष जल भराव तथा उसकी निकासी के नाम पर टेंडर जारी करने में ही शुभ-लाभ होता है।

फौज की भर्ती के नए नियमों के विरुद्ध पुलिस की .....

पेज एक का शेष

बाद करीब दोपहर 12 बजे पुलिस ने पर्याप्त संख्याबल नही होने बावजूद युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की तो युवा उग्र हो गए। युवाओं ने चारों डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी पास ही बने जिला उपायुक्त के निवास स्थान में घुस गए। इसके बाद गुस्साए युवाओं ने जिला उपायुक्त के निवास स्थान में पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वहीं ताऊ देवीलाल पार्क के समीप खड़ी पुलिस की पांच को गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। करीब डेढ़ घंटे तक युवा उपद्रव करते रहे। इसके बाद करीब डेढ़ बजे फरीदाबाद, नूंह से आये पुलिस बल और पलवल जिले की पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा फायरिंग कर युवाओं पर काबू पाया। पुलिस को हावी होता देख प्रदर्शनकारी युवा कैंप मार्किट की तरफ भाग निकले। इसी बीच पुलिस ने सड़क पर आने जाने वाले अनेक बेकसूर लोगों को भी हिरासत में ले लिया।

प्रशासन ने हालातों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट को भी बंद करने के आदेश दे दिए। मौके पर पहुंचे जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक मुकेश मल्होत्रा ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद पुलिस ने शहर के फौज की भर्ती की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों में जाकर वहां पहुंचे युवाओं को हिरासत में ले लिया तथा वहां से कोचिंग लेने वाले छात्रों के नाम व पते लेकर रात को ही अनेक युवाओं को हिरासत में ले लिया। कैम्प थाना में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। सूचना के अनुसार लगभग 72 युवाओं को हिरासत में लिया गया है।

इस उत्पात की सूचना गुप्तचर विभाग समय रहते दे देता और आंदोलन कारी युवाओं को यदि बस अड्डे पर ही रोक लिया जाता और उसी समय पर्याप्त पुलिस बल बुला लिया जाता तो पलवल के ये हालत नही बनते।

पार्किंग की नई योजना: स्कूलों व अस्पतालों पर तो रहम करे प्रशासन

फ़रीदाबाद (म.मो.) घनघोर हो चुकी पार्किंग की समस्या ने जब सड़कों पर चलना तक दूभर कर दिया तो प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो ही गया। नगर निगम व पुलिस द्वारा किये गये संयुक्त सर्वे द्वारा अनेकों स्थान पार्किंग के लिये चिन्हित किये गये हैं। इन स्थानों में नगर निगम के अपने भूखंड तो ठीक हैं लेकिन इसकी आड़ में स्कूलों पर कब्जा करना किसी तरह से भी उचित नहीं है।

विदित है कि ये तमाम स्कूल करीब 70 वर्ष पूर्व यानी कि शहर के निर्माण के समय ही बनाये गये थे। उसके बाद से अब तक आबादी का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन सरकारी स्कूलों की आवश्यकता कहीं अधिक है। यह बात अलग है कि शासन-प्रशासन ने इन स्कूलों को बुरी तरह से उजाड़ दिया है। इन स्कूलों को ठीक करने की आवश्यकता है न कि इनका इस्तेमाल बदलने की।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे पार्किंग बनाने का औचित्य सामान्य समझ के परे है। समझ नहीं आता कि वहां कोई क्यों पार्किंग करने आयेगा? इसके अलावा जिस तरह से इस कॉलेज एवं अस्पताल का काम बढ़ रहा है उसे देखते हुए इसे अतिरिक्त ज़मीन की आवश्यकता है। ईएसआई कार्पोरेशन ने इस बाबत राज्य सरकार एवं ज़िला प्रशासन से सम्पर्क किया है। यह तय है कि इस संस्थान को कम से कम पांच एकड़ और ज़मीन की आवश्यकता है।

शासन-प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान देने की जरुरत नहीं समझी कि बीके अस्पताल और ईएसआई मेडिकल कॉलेज को एक दूसरे से जोड़ना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच में मात्र डेढ़ दो एकड़ का भूखंड खाली पड़ा है जिसे विधायक सीमा त्रिखा ने अवैध राहुल कॉलोनी के विस्तार हेतु बचा रखा है। इसके विपरीत यदि दोनों संस्थानों को जोड़ दिया जाय तो सैकड़ों मेडिकल विद्यार्थियों को पोस्टमार्टम की ट्रेनिंग के लिये दो किलोमीटर का चक्कर काटकर बीके न जाना पड़े। इसी तरह समय-समय पर डॉक्टरों को भी एक दूसरे से सलाह मशवरे के लिये चक्कर काटकर आना-जाना पड़ता है। हाल ही में बीके अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज के बीच हुए समझौते के अनुसार डीएनबी कोर्स करने वाले डॉक्टर ईएसआई मेडिकल कॉलेज की लायब्रेरी में अध्ययन करने लगातार आया करेंगे।

वैसे भी पार्किंग की आवश्यकता शहर के व्यस्त बाजारों में अधिक है। इसके लिये इन सभी स्थानों पर नगर निगम के अपने भूखंड पर्याप्त हैं। तिकोना पार्क की ऑटो मार्केट में अवैध कब्जों को हटा कर भी काफ़ी स्थान उपलब्ध हो सकता है। यहां पर दर्जनों वाहन स्थाई तौर पर खड़े हैं। पुलिस को अपराध के नजरिये से भी उनकी जांच करके उन्हें वहां से हटवाना चाहिये।

पार्किंग की एक दूसरी समस्या सड़कों के किनारे बड़े वाहन खड़े करने की है। प्रशासन चाहे कितने भी पार्किंग स्थल बना ले ये वाहन वहां जाने वाले नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बाटा फ्लाईओवर से हार्डवेयर चौक वाली सड़क के दोनो ओर माल से लदे एवं खाली बड़े-बड़े ट्रक व ट्राले सड़क घेरे खड़े रहते हैं। ये कभी भी निर्धारित पार्किंग स्थलों पर जाने वाले नहीं हैं। यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है, वाहनों के ऐसे जमावड़े शहर में अनेकों जगह मौजूद हैं। इसी तरह एनएच दो में कई दुकानदारों ने अपने सामने 20-30 दुपहिया वाहन बिक्री के लिये खड़े कर रखे हैं, वे भी किसी पार्किंग में जाने वाले नहीं हैं। इन सब से निपटने के लिये तो पुलिस एवं प्रशासन को कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे।